

यूपीआई पर फीस

UPI Transaction Charges — क्या, क्यों और कितना?



Presentator:

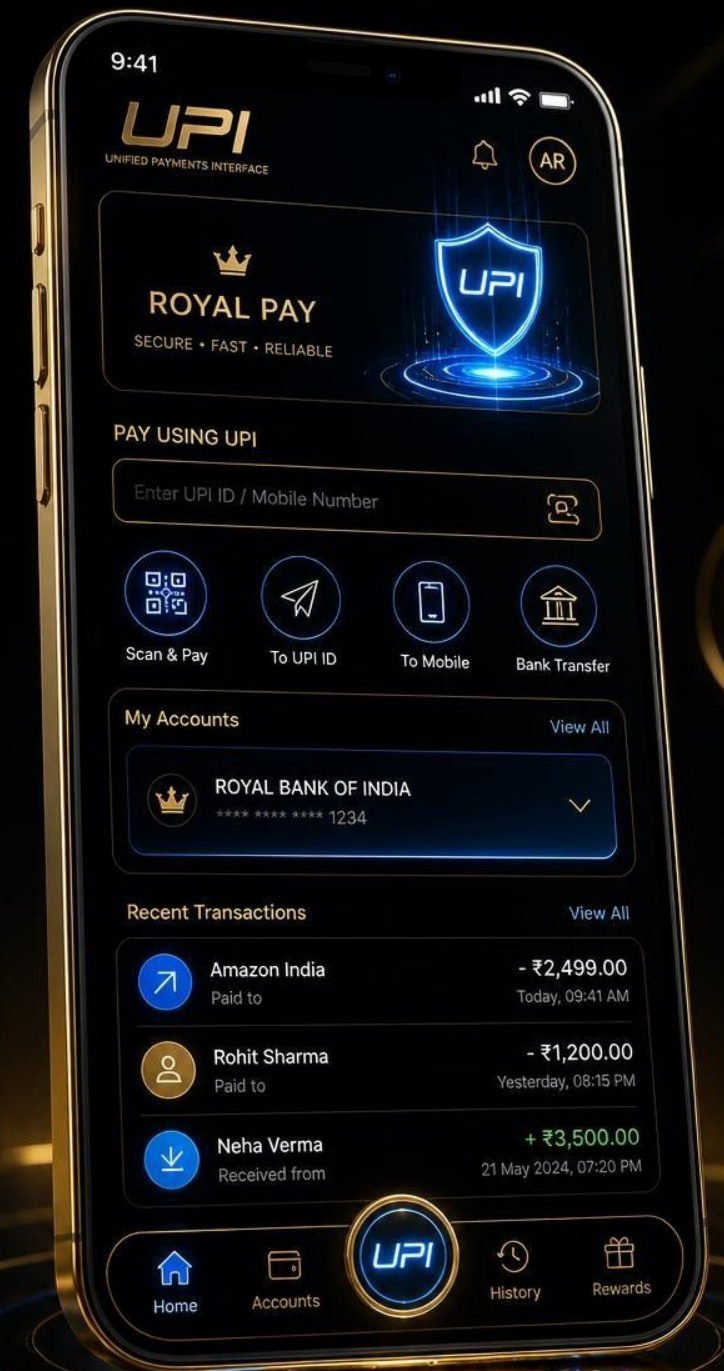
Dr. Suneil Kr Tripathi

Associate Professor
Faculty CSE & Consultant

September 2026

यूपीआई क्या है?

- UPI = Unified Payments Interface
- NPCI द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया
- मोबाइल से तत्काल बैंक-टू-बैंक ट्रांसफर
- 24×7 उपलब्ध — छुट्टी के दिन भी
- PhonePe, GPay, Paytm, BHIM जैसे ऐप्स
- रोज़ाना 66 करोड़+ लेन-देन (2026)
- विश्व का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम



यूपीआई की सफलता की कहानी

2016 — NPCI ने UPI लॉन्च किया

2020 — कोविड के बाद डिजिटल भुगतान में उछाल

2023 — 100 अरब लेन-देन का आंकड़ा पार

2024 — ₹200 लाख करोड़ से अधिक का लेन-देन

2025 — 10+ देशों में UPI स्वीकृत

2026 — रोज़ाना 66 करोड़+ ट्रांज़ैक्शन

सिंगापुर, UAE, फ्रांस, UK में UPI उपलब्ध

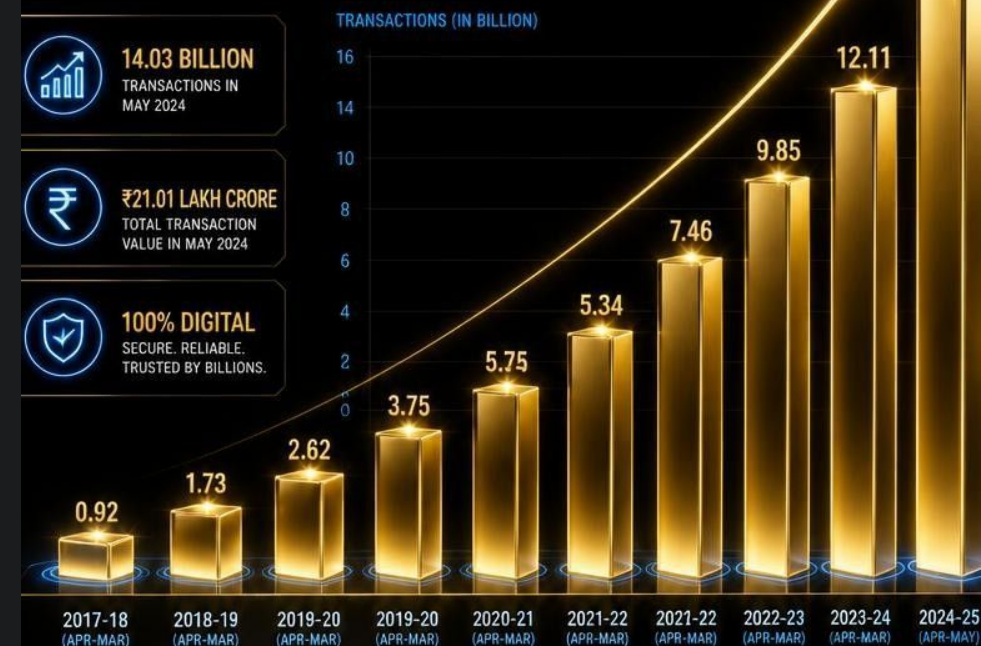
UPI

TRANSACTION GROWTH

POWERING A DIGITAL INDIA

FAST. SECURE. SEAMLESS.

MAY 2024
14.03
BILLION
TRANSACTIONS



14.03 BILLION
TRANSACTIONS IN
MAY 2024

₹21.01 LAKH CRORE
TOTAL TRANSACTION
VALUE IN MAY 2024

100% DIGITAL
SECURE. RELIABLE.
TRUSTED BY BILLIONS.

1.4+ BILLION
USERS

600+ BANKS
ON UPI

50+ COUNTRIES
UPI GLOBAL REACH

MILLIONS OF
TRANSACTIONS
EVERY SECOND

UPI ALWAYS FORWARD

Source: NPCI | Data as of May 2024

NPCI



यूपीआई पर फीस — क्यों?

- 💰 अब तक UPI लेन-देन पूरी तरह मुफ्त था
- 💰 सरकार ने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया
- 💰 साइबर सुरक्षा और सिस्टम अपग्रेड की ज़रूरत
- 💰 NPCI और बैंकों को रखरखाव लागत वहन करनी पड़ती है
- 💰 MDR (Merchant Discount Rate) से राजस्व जुटाने की योजना
- 💰 15 अक्टूबर 2026 से कुछ लेन-देन पर 0.4% MDR लागू
- ⚠️ ₹2,000 तक के लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं

MDR क्या है?

📌 MDR = Merchant Discount Rate (व्यापारी छूट दर)

📍 दुकानदार/व्यापारी से लिया जाने वाला शुल्क

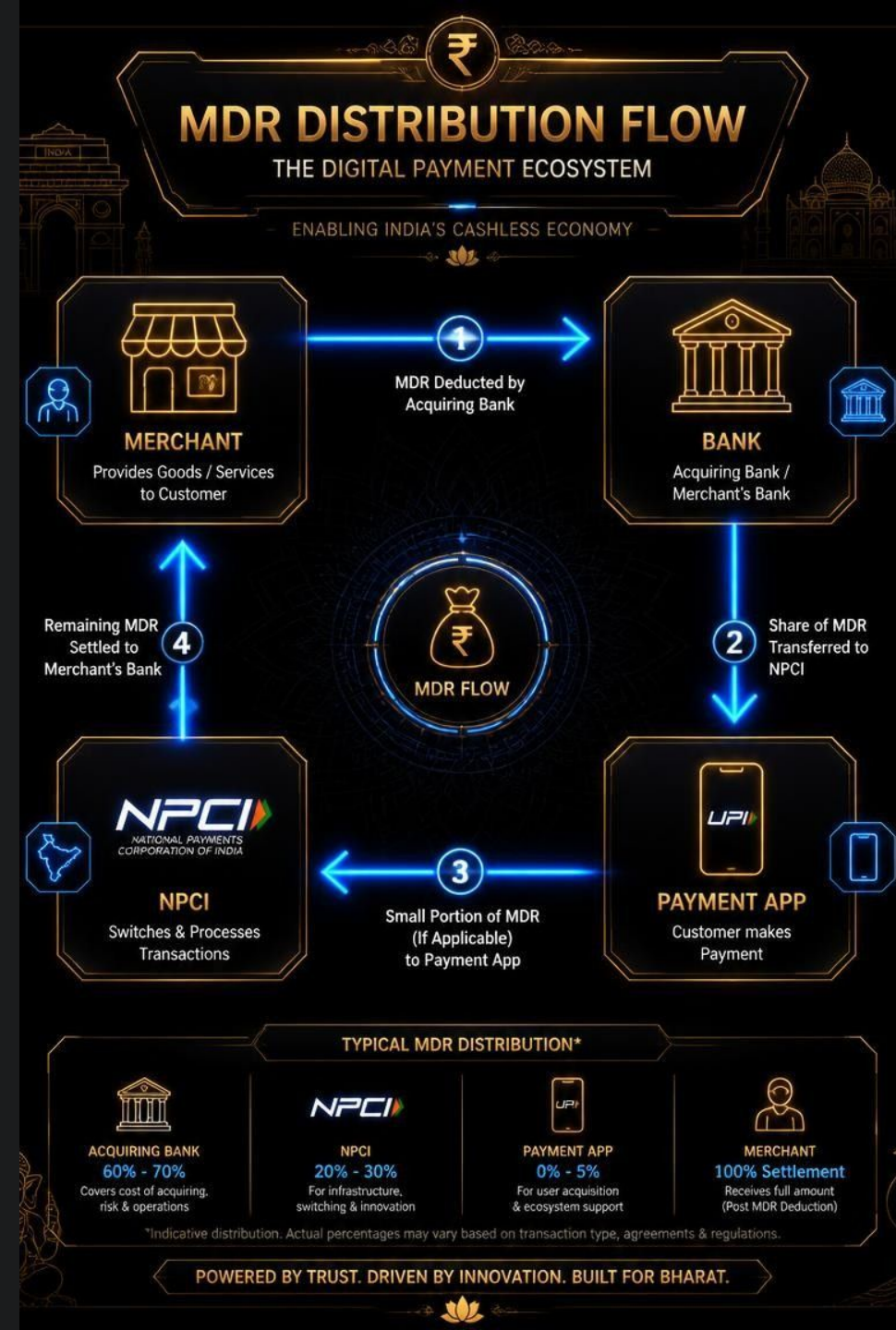
📌 बैंक, पेमेंट गेटवे और NPCI में बंटता है

📍 क्रेडिट कार्ड पर पहले से MDR लागू है (1.5–2%)

📌 UPI पर 0.4% MDR — केवल बड़े व्यापारिक लेन-देन पर

📍 ₹2,000 से अधिक के B2B/व्यापारिक लेन-देन पर लागू

📍 आम उपभोक्ता के P2P लेन-देन पर कोई असर नहीं



किस पर लगोगी फीस?

किस पर नहीं?

✓ फीस नहीं लगोगी

- व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) लेन-देन
- ₹2,000 तक के सभी लेन-देन
- आम उपभोक्ता के दैनिक भुगतान
- सरकारी सेवाओं का भुगतान
- छोटे दुकानदार (Small Merchants)

✗ फीस लगोगी

- ₹2,000 से अधिक के व्यापारिक लेन-देन
- बड़े व्यापारी (Large Merchants)
- B2B (Business to Business) भुगतान
- 0.4% MDR शुल्क लागू होगा
- 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी

विपक्ष का रुख — अमेरिकी दबाव?

- ● विपक्ष ने इसे "अमेरिकी दबाव की परिणति" बताया
- ● राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने का आरोप
- ● अमेरिकी पेमेंट नेटवर्क (Visa/Mastercard) को फायदा?
- ⇨ ● लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने किया विरोध
- ↘ ● UPI की सफलता से अमेरिकी नेटवर्क की ईर्ष्या
- 🕒 ● कई विपक्षी दलों ने संसद में उठाया मुद्दा
- ⚡ ● सरकार का जवाब: डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूती के लिए ज़रूरी





साइबर सुरक्षा — बढ़ता खतरा

- 🛡️ UPI उपयोग बढ़ने के साथ साइबर धोखाधड़ी भी बढ़ी
- 🛡️ 2025 में UPI फ्रॉड के 1.5 करोड़+ मामले दर्ज
- 🛡️ फिशिंग, स्क्रीन शेयरिंग, फेक QR कोड से ठगी
- 🛡️ MDR से मिले पैसे सुरक्षा में लगाए जाएंगे
- 🛡️ AI-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम विकसित हो रहा है
- 🛡️ RBI और NPCI मिलकर सुरक्षा मानक बना रहे हैं
- ⚠️ उपयोगकर्ता जागरूकता सबसे बड़ा हथियार

आम जनता पर असर — क्या डरें?

- 👤 आम उपभोक्ता के P2P लेन-देन पर कोई असर नहीं
- 👤 ₹2,000 तक की खरीदारी पर कोई शुल्क नहीं
- 🏪 बड़े व्यापारी MDR का बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं
- 🏪 वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की आशंका
- 💡 सरकार को निगरानी रखनी होगी
- 💡 MDR का भार आम जनता पर न पड़े — यह सुनिश्चित करना ज़रूरी
- ✓ छोटे व्यापारी और किसान सुरक्षित रहेंगे



UPI का वैश्विक विस्तार

- 🌐 10+ देशों में UPI स्वीकृत — 2025 तक
- 🌐 सिंगापुर, UAE, फ्रांस, UK, नेपाल, भूटान में उपलब्ध
- 🌐 G20 देशों में UPI को मान्यता
- 🌐 SWIFT का विकल्प बनने की दिशा में
- 🌐 भारत का डिजिटल कूटनीति में नया हथियार
- 🌐 विदेश में बसे भारतीय भी UPI से भुगतान कर सकते हैं
- 🏆 विश्व बैंक ने UPI को "डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर" का मॉडल माना





सरकार की चुनौतियाँ

- ✕ विपक्ष के राजनीतिक हमलों का जवाब देना
- ✕ MDR का बोझ आम जनता पर न पड़े — निगरानी ज़रूरी
- ✕ व्यापारी वर्ग द्वारा शुल्क उपभोक्ताओं पर डालने से रोकना
- ⇒ ✕ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश सुनिश्चित करना
- ↘ ✕ UPI की लोकप्रियता बनाए रखना
- 🌀 ✕ साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाना
- 🌀 ✕ दीर्घकालिक वित्तीय ढांचे को मजबूत करना

निष्कर्ष — आगे की राह

🔑 UPI भारत की डिजिटल क्रांति की रीढ़ है

🔑 MDR एक आवश्यक कदम — पर सावधानी ज़रूरी

🔑 ₹2,000 तक की सीमा आम जनता की सुरक्षा करती है

🔑 डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश अनिवार्य है

🔑 साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी

🔑 UPI का वैश्विक विस्तार भारत की शक्ति है

★ डिजिटल भारत — सशक्त भारत!

SPACE & BEYOND
REACHING NEW HORIZONS

EDUCATION & SKILLS
EMPOWERING YOUNG MINDS

HEALTHCARE FOR ALL
BUILDING A HEALTHY NATION

"सियासत अपनी जगह, मगर देश के वित्तीय ढांचे में दीर्घकालिक बदलाव का स्वागत होना चाहिए।"

Presentator: Dr. Suneil Kr Tripathi | Associate Professor, Faculty CSE & Consultant